

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III  
( भारतीय अर्थव्यवस्था ) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

7 अगस्त, 2020

“आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा ने ब्याज दरों को व्यापक बाजार की उम्मीदों के विपरीत रखा है। इस आलेख में हम जानेंगे कि किस प्रकार मुद्रास्फीति और वृद्धि इस निर्णय का कारण बनी और इसके अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।”

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो दर को 4 प्रतिशत पर पूर्ववत् रखा गया है। हालांकि, बैंक ने उदार रख बनाये रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने केंद्रीय बैंक के रुख को उदार बनाए रखकर कोविड-19 संकट से पीड़ित अर्थव्यवस्था की मदद के लिए जरूरी होने पर भविष्य में कटौती का संकेत दिया। आरबीआई ने इस साल फरवरी से नीतिगत दरों में 115 आधार अंकों की कमी की है। गुरुवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में, आरबीआई ने तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को बाहर निकालने के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को भी हरी झंडी दे दी है।

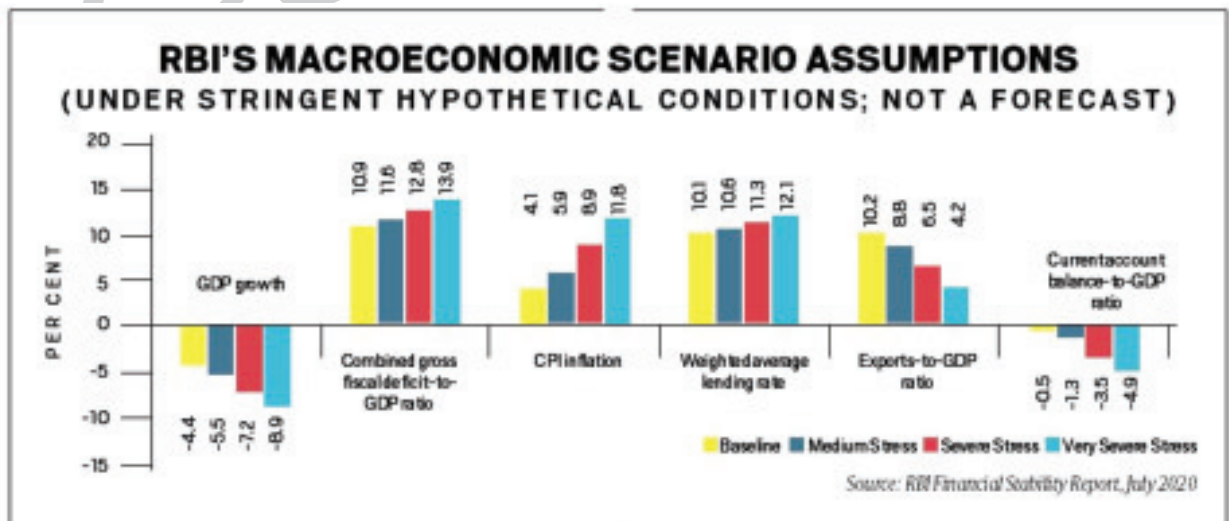
**मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में कमी क्यों नहीं की?**

जहाँ एक तरफ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई का उदाररुख जारी है, वहीं दूसरी तरफ नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं कर आरबीआई ने बैंक को अधिक उधार देने की क्षमता को कम किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति, जून में 6.09% से बढ़कर मार्च में 5.84% हो गई, जिससे RBI की मध्यम अवधि का लक्ष्य 2-6% हो गया। ऐसा लगता है कि यह एक प्रमुख भयसूचक चिह्न था जिसने एमपीसी के सर्वसम्मत निर्णय को प्रेरित किया। इसके अलावा, श्री दास ने घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता भी जताई है।

**महंगाई को लेकर RBI क्यों चिंतित है?**

आरबीआई गवर्नर ने यह स्पष्ट किया कि अप्रैल-मई 2020 के हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। पूर्वी भारत में बाढ़, लॉकडाउन से संबंधित व्यवधान और पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च करों, दूरसंचार शुल्क में बढ़ोतरी, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, स्टील की कीमतों और सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के उद्देश्य को खाद्य पदार्थों की कीमतों की तीव्र वृद्धि और अधिक अस्पष्ट बना दिया है।

दो महीने के अंतराल के बाद जून में हेडलाइन मुद्रास्फीति और अप्रैल-मई के लिए मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में अनिश्चितता देखी गयी है। कोविड-19 की वजह से भोजन और गैर-खाद्य कीमतों दोनों के साथ आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान आया है। हालांकि प्रमुख सब्जियों



में बढ़ते मूल्य के दबाव को समाप्त करना बाकी है, दालों के मामले में मांग-आपूर्ति संतुलन को देखते हुए प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थ एक परेशानी के रूप में भी उभर सकते हैं।

RBI का मानना है कि गैर-खाद्य श्रेणियों का मुद्रास्फीति दृष्टिकोण अनिश्चितता से भरा है। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और बढ़ती परिसंपत्ति की कीमतें भी इस दृष्टिकोण के जोखिम को बढ़ाती हैं। वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, लेकिन बड़े अनुकूल आधार प्रभावों से 2020-21 की दूसरी छमाही में मध्यम रह सकती है।

### **पिछली ब्याज दरों में कटौती का क्या असर रहा?**

RBI ने दावा किया है कि फरवरी 2019 से रेपो दर में 250 आधार अंकों की क्रमवार कमी अर्थव्यवस्था के माध्यम से पैसे, बांड और क्रेडिट बाजारों में ब्याज दरों को कम करते हुए काम कर रही है। मई में, MPC ने अपनी समायोजन नीति के रुख को बनाए रखते हुए रेपो दर को 40 बीपीएस कम करते हुए 4% कर दिया था। वास्तव में, पिछले सात महीनों में, एमपीसी ने पहले ही 115 बीपीएस की रेपो दर को घटा दिया है, हालांकि बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए हस्तांतरण को अभी भी पूरी तरह से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

### **अर्थव्यवस्था का RBI आकलन क्या है?**

इसके अनुसार जून में देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार होने लगा था। हालांकि, कई शहरों और राज्यों में कोविड-19 के फिर से बढ़ते संक्रमण ने नए सिरे से लॉकडाउन को लागू करने के लिए मजबूर किया है, जिससे समस्या फिर से खड़ी होने लगी है। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख सहित आरबीआई और कई विशेषज्ञों ने कहा है कि खरीफ की बुआई में प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रिकवरी मजबूत होने की उम्मीद है।

RBI के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण का जवाब देने वाली विनिर्माण कंपनियों घरेलू मांग को धीरे-धीरे Q2 से उबरने और 2021-22 की Q1 से बेहतर होने की उम्मीद करती हैं। हालांकि, संपूर्ण रूप से वर्ष 2020-21 के लिए, वास्तविक जीडीपी वृद्धि नकारात्मक होने की उम्मीद है। महामारी की प्रारंभिक रोकथाम के दृष्टिकोण में सुधार हो सकता है। लेकिन महामारी का व्यापक फैलाव, एक सामान्य मानसून का ना होना और वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता नकारात्मक जोखिम की ओर इशारा करता है।

### **क्या RBI, दरों में गिरावट और विकास को बढ़ावा देने के लिए तरलता पर निर्भर करता है?**

फरवरी 2020 के बाद से आरबीआई द्वारा घोषित तरलता उपायों का मूल्य लगभग 9.57 लाख करोड़ रुपये है- जो 2019-20 के नॉमिनल जीडीपी के लगभग 4.7% के बराबर है। आरबीआई ने कहा कि अब तक के तरलता उपायों ने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए ब्याज लागत को कम करने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप कम नीतिगत दरों का प्रभावी प्रसारण और वित्तीय स्थितियों में सुधार हुआ है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और म्यूचुअल फंडों की स्थिति मार्च में कोविड-19 से उत्पन्न संकट के बाद स्थिर हो गई है।

आरबीआई ने गुरुवार को नीतिगत रेपो दर पर 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है, जिससे प्रत्येक नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को 5,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे हाउसिंग सेक्टर, एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को फंड के प्रवाह में सुधार होने की उम्मीद है। ऋण पुनर्गठन जैसे उपायों का उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों की तरलता स्थिति में सुधार करना है।

### **तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए नया ऋण पुनर्गठन ढांचा क्या है?**

चूंकि ऋण चुकौती पर रोक 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी, इसलिए बैंक और आरबीआई को बैंड लोन में वृद्धि होने की उम्मीद है। मार्च 2021 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां कुल ऋण का 14.7% तक बढ़ सकती हैं। महामारी से प्रभावित तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, आरबीआई ने 1 मार्च, 2020 तक 30 दिनों से अधिक समय तक डिफॉल्ट करने वालों के लिए टाइम रिस्ट्रक्चरिंग विंडो को खोला है। कॉर्पोरेट और बड़े ऋणों के पुनर्गठन के लिए, सख्त ऋणों की निगरानी और मानदंडों के पालन को बैंड लोन को रोकने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए, बैंक 31 दिसंबर, 2020 तक एक संकल्प योजना की शुरुआत कर सकते हैं और इसे 30 जून, 2021 तक बढ़ा सकते हैं।

बड़े एक्सपोजर के पुनर्गठन के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन की आवश्यकता होगी और के वी कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया होगी। अपेक्षित ऋण घाटे के प्रभाव को कम करने के लिए, बैंकों को रेजल्यूशन के तहत ऐसे खातों के लिए 10% प्रावधान करने की आवश्यकता है। एकल उधारकर्ता के लिए कई उधारदाताओं के मामले में, बैंकों को अंतर-लेनदार समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

**संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )**

प्र. हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 2014 को किया गया था।
2. मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से 4 सदस्य RBI से होते हैं।
3. भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1                      (b) केवल 3  
(c) 1 और 3                      (d) इनमें से कोई नहीं

**Expected Question (Prelims Exams)**

Q. Recently, in the meeting of the Monetary Policy Committee, the RBI has kept the interest rates unchanged. Consider the following statements in the context of Monetary Policy Committee: -

1. It was formed in the year 2014 to make interest rate determination more useful and transparent.
2. Of the six members of the Monetary Policy Committee, 4 are from RBI.
3. The Deputy Governor of the Reserve Bank of India is the ex-officio Chairman of the Committee.

Which of the statements given above is / are correct?

- (a) 1 only                      (b) 3 only  
(c) 1 and 3                      (d) None of these

**संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )**

प्र. अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका की व्याख्या करें और बताइए कि वर्तमान में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? चर्चा कीजिये।

Q. Explain the role of RBI in the economy and discuss what will be the effect on the economy by the RBI keeping interest rates unchanged at present?